अध्याय 3

बाल कल्याण समितियां की कार्यप्रणाली

सीडब्ल्यूसी ने न तो उनके सामने पेश किए गए बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के संबंध में आदेश जारी करने के बाद उनकी प्रगति का पालन सुनिश्चित किया और न ही पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट पोर्टल पर आदेश अपलोड किया। उन्होंने फेशियल रिकॉग्नीशन सिस्टम पर बरामद बच्चों की तस्वीरें भी अपलोड नहीं की ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके, जो माता-पिता और बच्चों के लिए अलगाव के आघात को कम करने हेतु चिंता की कमी को दर्शाता है।

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) का मुख्य कार्य बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उचित पुनर्वास या वापसी सुनिश्चित करना तथा माता-पिता, अभिभावकों, योग्य व्यक्तियों, बाल-गृह अथवा उपयुक्त सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देना है।

जब भी किसी बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे पुलिस/डीसीपीयू/सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठन और किसी भी लोक सेवक, आदि द्वारा बच्चे पाये जाने के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- इसके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बच्चे को प्राप्त करना और संज्ञान लेना;
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर पूछताछ करना;
- देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की घोषणा करने के लिए पूछताछ करना, इन बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उचित पुनर्वास या बहाली सुनिश्चित करना;
- इस संबंध में माता-पिता या अभिभावकों या उपयुक्त व्यक्तियों या बाल गृहों या उपयुक्त सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना;
- उचित जांच के बाद अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना, इत्यादि।

सीडब्ल्यूसी की बच्चे को उसके माता-पिता, अभिभावकों, उपयुक्त व्यक्ति या बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) को भेजने के लिए जांच करने और आदेश पारित

करने की ज़िम्मेदारी है। अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल गृह छोड़ने वाले किसी भी बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक आफ्टर केयर होम में रखा जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच किए गए चार सीडब्ल्यूसी के कामकाज का आकलन किया और निम्नलिखित चूक/कमियाँ देखीं:

3.1 सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों की प्रगति का अनुवर्तन नहीं किया गया

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 19(18) के अनुसार, मामले को अंतिम रूप से निपटान करते समय, सीडब्ल्यूसी मामले के निपटान की तारीख से एक महीने के भीतर और उसके बाद छः महीने तक हर महीने में एक बार और उसके बाद कम से कम एक साल तक तीन महीने में एक बार के लिए या जब तक सीडब्ल्यूसी उचित समझे, बच्चे के अनुवर्ती कार्रवाई की एक तारीख देगा।

लेखापरीक्षा ने एक नमूना जांच किए गए सीडब्ल्यूसी में पाया कि संबंधित सीसीआई/डीसीपीयू द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, जैसा कि आदेश में उल्लेखित था, और सुनवाई की अगली तारीख में बच्चों को सीडब्ल्यूसी में पेश नहीं किया गया। फिर भी, सीडब्ल्यूसी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समिति की बैठकों में बच्चे की प्रगति की समीक्षा की जाती है। व्यक्तिगत मामलों की आवधिक समीक्षा भी संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती है और आवश्यक समझे जाने वाले निर्देशों को आवश्यक हस्तक्षेपों के साथ पारित किया जाता है, अर्थात् बहाली, पुनर्वास, संरक्षण का हस्तांतरण या बच्चे को सीसीआई में बनाए रखने की अनुमति देना, जैसा भी मामला हो। साथ ही, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

3.2 सीडब्ल्यूसी द्वारा फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए कार्रवाई में विलम्ब

बच्चे का परिवार से अलग होना बच्चे और परिवार दोनों के लिए दुखदायी होता है। एक लापता बच्चे के संबंध में एक याचिका के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने गंभीर चिंता व्यक्त की और देखा कि जनवरी 2016 से दिसंबर 2018 तक लापता बच्चों के 19,916 मामलों में से केवल 14,756 बच्चों का पता लगाया गया और उनके परिवार के सदस्यों के साथ फिर से जोड़ा गया जबकि, 5,160 बच्चों का पता लगाया जाना बाकी है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों (22 जनवरी 2019) पर विभिन्न हितधारकों के

बीच एक बैठक आयोजित की गई थी (28 मार्च 2019), जिसमें निर्णय लिया गया था कि सीडब्ल्यूसी को बरामद बच्चों की तस्वीरें फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर (एफआरएस) पर अपलोड करनी थी ताकि लापता बच्चों के विवरण का मिलान किया जा सके। हालांकि, 2018-19 से 2020-21 के दौरान लापता बच्चों के रिकार्ड के प्रति केवल सीडब्ल्यूसी-II, लाजपत नगर और सीडब्ल्यूसी-X, अलीपुर ने एफआरएस में क्रमशः 56 और 12 तस्वीरें अपलोड कीं और अन्य सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किए गए बच्चों के विवरण और तस्वीरें अपलोड और जांच नहीं की गई।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एफआरएस का रखरखाव दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है और यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी के अध्यक्षों/सदस्यों का विवरण प्रदान किया जा रहा है। हालांकि, जवाब से सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किए गए बच्चों में से लापता बच्चों की पहचान करने के लिए एफआरएस का उपयोग हेतु कार्रवाई करने में विलम्ब का कारण प्रदान नहीं करता है।

अनुशंसा सं. 5: बाल कल्याण समितियों अपने सामने लाए गए बच्चों की तस्वीरें फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके।

3.3 सीडब्ल्यूसी के आदेश अपलोड करने में विफलता

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के उप नियम 19 (21) के अनुसार, एक बच्चे के संबंध में सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित सभी आदेशों को बच्चे की निजता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए एक निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। चूंकि बाल देखभाल सामाजिक महत्व का मुद्दा है, इसलिए पोर्टल पर सूचना डालने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और सार्वजनिक डोमेन में जानकारी के लिए जवाबदेही किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के लिए खुली है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसी कोई प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सभी सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध पोर्टलों और ऐप्स तक त्वरित पहुंच के लिए टैब प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, डीडब्ल्यूसीडी ने डीसीपीसीआर के साथ संयुक्त रूप से दिसंबर 2021 में एनआईसीएसआई के साथ एक किशोर न्याय एमआईएस विकसित करने के लिए एक समझौता किया है ताकि सीडब्ल्यूसी के समक्ष लाए गए और सीसीआई में रखे गए प्रत्येक बच्चे की प्रगति को ट्रैक और मॉनिटर किया जा सके जो पारदर्शिता और गोपनीयता को बनाए रखने में सक्षम होगा और साथ ही उचित हस्तक्षेप के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा प्रदान करेगा। तथ्य यह

है कि सीडब्ल्यूसी के आदेश आवश्यकतानुसार सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखे जाते हैं।

3.4 सीडब्ल्यूसी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 89 सीडब्ल्यूसी के कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य प्रशिक्षण (न्यूनतम 15 दिनों की अवधि के लिए) निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर्मचारियों को अपेक्षित अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अभाव में, सीडब्ल्यूसी के कर्मचारी सांविधिक ज़िम्मेदारीयों और विशिष्ट काम की आवश्यकताओं के मामले में पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि बाल कल्याण समिति में नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति का कामकाज बाधित न हो। सीडब्ल्यूसी सदस्यों को जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक दिए गए प्रशिक्षणों का विवरण भी दिया गया। हालांकि, नमूना जांच किए गए सीडब्ल्यूसी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कर्मचारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

3.5 बच्चों और परिवारों को प्रतीक्षालय उपलब्ध नहीं कराया गया

सीडब्ल्यूसी की स्थापना के लिए आईसीपीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चों और परिवारों को एक प्रतीक्षालय प्रदान किया जाना था। यह देखा गया कि चार चयनित सीडब्ल्यूसी में से केवल दो में प्रतीक्षालय उपलब्ध था, अर्थात् सीडब्ल्यूसी-III, किंग्सवे कैंप और सीडब्ल्यूसी-V, दिलशाद गार्डन।

इस प्रकार सीडब्ल्यूसी, जिनकी कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण में बड़ी भूमिका होती है, वे इस तरह से काम नहीं कर रहे थे जिससे उनकी क्षमता और इरादे में विश्वास पैदा हो।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सभी सीडब्ल्यूसी में बच्चों, परिवारों और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में पर्याप्त जगह है और उनका उचित रखरखाव किया जाता है। हालांकि, जवाब चार चयनित सीडब्ल्यूसी में से दो द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुरूप नहीं है, जिसने पुष्टि की थी कि शेष दो चयनित सीडब्ल्यूसी अर्थात् सीडब्ल्यूसी-II (दक्षिण) और सीडब्ल्यूसी-X (उत्तर) में कोई अलग से प्रतीक्षालय नहीं था।

3.6 सीडब्ल्यूसी को काउंसलर सेवाएं प्रदान नहीं की गई

आईसीपीएस के दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि जिस बाल गृह में सीडब्ल्यूसी अपनी कार्यवाही कर रही है, वह उन दिनों में, सीडब्ल्यूसी को काउंसलर का सहयोग प्रदान करेगा जब बैठक हो रही हो। ऐसे काउंसलर बच्चे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर विचार करते हुए, बच्चे के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका तय करने में सीडब्ल्यूसी की मदद कर सकते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि चार में से दो[6] सीडब्ल्यूसी को काउंसलर की सेवा प्रदान नहीं की गई थी जिससे बच्चे अपनी जरूरतों के संबंध में पेशेवर मूल्यांकन से वंचित रहे थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि डीएसएलएसए और डीसीपीयू स्टाफ के काउंसलर पहले से ही प्रत्येक सीडब्ल्यूसी में तैनात हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने काउंसलर की अनुपलब्धता की पुष्टि की थी।

[6] सीडब्ल्यूसी-II (दक्षिण), लाजपतनगर और सीडब्ल्यूसी-III (केंद्रीय), किंग्सवे कैंप